As far as international intervention for checking their mental assessment and other things are concerned, India firmly believe that issues between India and Pakistan can be resolved bilaterally and there is no need of third intervention.

*402. [The questioner (Shri Dwijendra Nath Sharmah) was absent. For answer vide page 28 infra].

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का कारोबार

*403. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'** : †

श्री राम जेठमलानी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का कारोबार वर्ष 2006 तक 1,96,105 करोड़ रुपए तक होने की आशा है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या आकलन है;

(ग) क्या इस कारोबार में राज्यों की भागीदारी का भी आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) से (घ) एक विवरण-पत्र राज्य सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक उच्चतर विकास दर का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर गठित दसवीं पंचवर्षीय योजना कार्यकारी दल ने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए वर्ष 2006-07 में 2,23,000 करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

† सभा में यह प्रश्न श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' द्वारा पूछा गया।

I.T. business

†*403 SHRI RAJIV RANJAN SINGH 'LALAN': ††
SHRI RAM JETHMALANI:

Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that business of information technology industry is expected to be Rs. 1,96,105 crores by the year 2006;

(b) if not, the assessments made in this regard;

(c) whether the share of States has also been assessed in this business; and

(d) if so, the details thereof, State-wise?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ARUN SHOURIE): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Rajya Sabha.

Statement

(a) A higher growth rate has been projected for the Information Technology industry.

(b) The Tenth Five Year Plan Working Group on Information Technology sector has targeted a turnover of Rs. 2,23,000 crore for the Information Technology industry in the year 2006-07.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': सभापति महोदय, सरकार ने उत्तर में यह कहा है कि पंचवर्षीय योजना के समाप्ति वर्ष 2007 तक 2,23,000 करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है। इसी [illegible] में 14 अगस्त को प्रश्न संख्या 343 के उत्तर में सरकार ने यह कहा था कि इस वर्ष 64,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है और इस कारोबार में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं समझता हूं कि यह जो वृद्धि की दर है, इससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और इस कारोबार में वृद्धि की

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rajiv Singh 'Lalan'

दर को बढ़ाने के लिए क्या योजना तैयार की है? चूंकि इस कारोबार में बड़ी कंपनियों के साथ छोटी कंपनियां भी लगी हुई हैं, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि बड़ी कंपनियों का शेयर कितना है और छोटी कंपनियों का शेयर कितना है?

श्री अरूण शौरी: सर, क्वेश्चन का जो दूसरा भाग है उसका मैं पहले जवाब दे दूं। हमारी एक्सपोर्ट में जो 5 बड़ी कम्पनीज हैं–टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज, इंफोसिस टेक्नॉलोजी, विप्रो, सत्यम और एचसीएल टेक्नॉलोजी इनका 30 परसेंट शेयर है। सर, अगली जो 5 हैं और उनको भी मिलाया जाए तो 37 परसेंट शेयर हो जाता है और जो सबसे बड़ी 20 कम्पनीज हैं एक्सपोर्ट में उनका 44 परसेंट शेयर है। तो 56 परसेंट छोटी–छोटी कम्पनियों का शेयर है। सर, दूसरे, जो टोटल टर्न ओवर है उसमें जो सबसे बड़ी 5 कम्पनीज हैं–टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, विप्रो, सत्यम और एचसीएल टेक्नॉलोजी उनका भी 30.3 परसेंट शेयर है और जो पहली 10 कम्पनीज हैं उनका 36.69 परसेंट शेयर है। दूसरी बात जो मेम्बर साहब ने कही कि टू मीट द टार्गेट, क्या योजनाएं तैयार की जा रही हैं, सर, बात यह है कि कई स्टडीज हैं मेकिन्न कार्पोरेशन की है, अर्नेस्ट एंड यंग की है एक इंटरनेशनल डाटा कारपोरेशन में यूएस की कम्पनी उनकी इंडियन सब्सिडयरी की है जिसमें कई फोरकास्ट किए गए हैं जो कि एक दूसरे से थोड़े से अंतर में हैं। हमारा जो प्लानिंग कमीशन है उसकी वर्किंग ग्रुप का भी एक फोरकास्ट है और बहुत ही कई तरह के इंसेंटिव दिए गए हैं बजट में। मुझे याद है कि 10–12 तरह के इंसेंटिव जब श्री यशवंत सिन्हा जी थे उन्होंने और अब श्री जसवंत सिंह जी ने दिए हैं और टैक्स इंसेंटिव का बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। उसके अलावा कंट्री में सोफटवेयर टेक्नॉलोजी पार्क बनाई गई हैं, तकरीबन 30 के करीब हैं और जो 80 परसेंट हमारी इंफार्मेशन टेक्नालोजी के एक्सपोर्ट हैं, सर बहुत खुशी की बात है कि उन टेक्नॉलोजी पार्क से यह किए जा रहे हैं। उसके अलावा यह एफर्ट किया जा रहा है कि जो इंडिविज्युअल यूनिट हैं उनको भी एक्सपोर्ट टेक्नॉलोजी पार्क माना जाए–एक वर्च्युअल पार्क माना जाए अगर वह कुछ कंडीशंस मीट करती हैं, जैसे कि अगर वे बांडिंग के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि कस्टम आफिसर आकर देख सकें कि उनमें क्या पार्ट आते हैं और सिर्फ वही यूज होते हैं और वहीं से माल एक्सपोर्ट होता है या सोफटवेयर एक्सपोर्ट होता है तो हार्डवेयर में उस टेक्नालोजी यूनिट को टेक्नालोजी पार्क का दर्जा दिया जाएगा और फिर सारे इंसेंटिव उनको उपलब्ध कराए जाएंगे।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': महोदय, जो सूचना प्रोद्योगिकी क्षेत्र है इससे रोजगार सृजन के मामले में काफी सफलता मिल सकती है और काफी रोजगार सृजन किए जा सकते हैं। लेकिन प्रश्न का "ग" भाग जो राज्यों की भागीदारी के संबंध में है उस पर सरकार का उत्तर नकारात्मक है। जब तक राज्यों की भागीदारी इस व्यापार में, कारोबार में नहीं होगी तब तक हम इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकेंगे और अगर हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो रोजगार के सृजन का जो लक्ष्य है उसको भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सरकार से यह जानना चाहेंगे कि राज्यों को इसमें

भागीदार बनाने के लिए सरकार ने क्या उनके स्तर पर बातचीत करने के लिए उनके यहां भी कारोबार को बढ़ाने के लिए उनको इसमें इंवोल्वड करने के लिए क्या कोई योजना बनाई है? और दूसरा, रोजगार से ही जुड़ा हुआ है कि आज इंफार्मेशन और टेक्नॉलोजी के जो लोग नौकरी पाने के लिए विदेशों में जाते थे उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं, वीजा में काफी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि जो विभिन्न प्रकार के वीजा हैं उनमें क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या सरकार ने उनको आइडेंटिफाई किया है और उन दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार के स्तर पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

श्री अरूण शौरी: सर, एक्च्युअली बहुत खुशी की बात है कि One of the reasons, on account of which there has been fast growth in many sectors in India in the last few years, including Information Technology, is that there is actually a competition amongst States और जिसको सेंटर एनकरेज भी करती है। आप देखेंगे कि कर्नाटक में अब तमिलनाडु की जो पार्क बनी है उसमें तथा अभी सर, केरल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंवेस्टर्स मीट आर्गनाइज की थी, उनमें पूना जैसे शहर के बीच में और आन्ध्र में इन सब में कम्पटीशन चल रहा है इंवेस्टर को एट्रेक्ट करने का। सर, अभी मैं वेस्ट बंगाल में गया था वहां भी उन्होंने एक साल्ट लेक सिटी से छह गुणा बड़ी सिटी बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और उसमें आईबीएम, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो और कई काल्स सेंटर्स की फर्म्स की बिल्डिंग्स का आलरेडी काम शुरू हो गया है। उसके कारण साफटवेयर टेक्नॉलोजी पार्ट्स, हार्डवेयर पार्ट्स, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट्स बनाकर स्टेट्स एक-दूसरे से कम्पीट कर रही हैं। अगर मेम्बर साहब चाहें और आपकी इजाजत हो तो मैं बतलाऊं कि रेट आफ ग्रोथ साफटवेयर एक्सपोर्ट में डिफरेंट स्टेट्स का क्या है और इलेक्ट्रानिक्स प्रोडक्शन क्या है। सर, वे लम्बी टेबल्स हैं, अगर आप कहें तो मैं दो-तीन पढ़ देता हूं, नहीं तो उनको बता दूंगा।

श्री सभापति: आप पढ़ दीजिए।

श्री अरूण शौरी: सर, मैं पढ़ देता हूं। जैसे कर्णाटक में रेट ऑफ ग्रोथ 25 परसेंट का रहा है। तकरीवन 12350 करोड़ का एक्सपोर्ट सिर्फ कर्णाटक से हो रहा है। सर, तमिलनाडु से रेट ऑफ ग्रोथ 26 परसेंट रहा है और उनका एक्सपोर्ट पिछले साल में 6305 करोड़ का रहा है। महाराष्ट्र में 20 परसेंट ग्रोथ है और 5500 करोड़ का उनका एक्सपोर्ट हो चुका है। आन्ध्र प्रदेश में ग्रोथ 31 परसेंट है और पिछले साल उनका एक्सपोर्ट 3668 करोड़ का था। इसी तरह और स्टेट्स के भी हैं। कई नई स्टेट्स जैसे हरियाणा, इनकी इन्फारमेशन टेक्नालाजी इनेबल्ड सर्विसिज में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है जबकि और जगह पर उतनी नहीं हुई है। इन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। सर, इन सब चीजों को करने के लिए, कई स्टेट्स ने इसको प्रमोट करने के लिए कई स्टेप्स उठाये हैं।

सर, दूसरा क्वेश्चन था कि वीज़ा में क्या डिफिकल्टी आ रही है। सर, यह रियल प्राब्लम है क्योंकि अब बाकी कंट्रीज में भी, इंडियन आरिजिन्स के लोग और वहां की फार्मस की आउट सोर्सिंग इंडिया में अब इस पैमाने पर पहुंच गई है कि उसके अगेंस्ट बैकलैश है। इसके बारे में सरकार कई चीजें कर रही है। जसवंत सिंह जी ने इस पर मीटिंग भी ली थी और उसमें इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटिव भी थे। सर, मैं अब उस पर आता हूं। दो तरह के मेन वीज़ाज आईटी के लिए लिये जाते हैं। एक तो एच-1बी वीज़ा है जो कि स्पेशिलिटी आक्युपेशनल वर्कर्स के लिए दिया जाता है। दूसरा एल-1 वीज़ा है जो कि इंटर कम्पनी ट्रांसफरीज के लिये दिया जाता है। तीसरा जो कि एक स्मालर प्रपोरशन है वह वी-1 वीज़ा है जो टेम्परेरी बिजनेस विजीटर्स के लिए दिया जाता है। एच-1 बी वीज़ा मोस्ट कामन टाइप का वीज़ा है और उसमें प्रसीजर यह है कि जो एम्पलायर है, जैसे कि एक इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स को एम्पालय करना चाहता है तो पहले वह पिटीशन करता है कि मुझे इस व्यक्ति की जरूरत है और मेरे पास ऐसे स्किल के और लोग नहीं हैं। इसके कारण पहले वह वीज़ा तीन साल के लिए दिया जाता है, that can be extended to a maximum of six months.

सर, उसको एक लिमिट यू एस में 95 थाउजेंड की रखी गई और इस साल शंका है कि शायद उसको डिक्रीज़ करके 65 थाउजेंड कर दिया जायेगा। उसके लिए हम कार्यवाही कर रहे हैं। L-1 visas are designed for inter-company transferees. एक कम्पनी है, जैसे–इन्फोसिस अपना आफिस वहां इस्टेबिलिश करता है तो वह एल-1 वीज़ा पर अपने प्रोफेशनल को ले जा कर अपने ही सबसीडियरीज में ट्रांसफर कर सके और उनको लोकेट कर सके क्लाइंट के आफिस में, उनसे वह फिर काम करवा सकें ···।

श्री सभापति: बस हो गया।

श्री अरूण शौरी: इन दोनों तरह के वीज़ाज में काफी बैकलैश हुआ है हम उसमें काफी सचेत हैं और इंडस्ट्री के साथ हम काम कर रहे हैं।

SHRI S.P.M. SAYEED KHAN: Thank you, Mr. Chairman, Sir. I would like to know from the hon. Minister whether the income generated by the call centres like info companies is also included in making this assessment? If so, what is the percentage of income generated by these companies out of the total IT business income?

SHRI ARUN SHOURIE: Sir, the total IT and electronics business is about Rs. 97,400 crores in the year ending March; hardware in that case is about Rs. 37,500 crores and software and IT enabled services are Rs. 59,900 crores. The Information Technology enabled services which are mainly the call-centres and so on within the software services is

Rs. 11,700 crores. It is already 2-1/2 billion dollars and we expect it will grow by almost by a billion dollar more.

श्री एस. एस. अहलुवालिया: सभापति महोदय, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी का व्यवसाय घर घर का सपना हो गया है। हरेक नौजवान हरेक नवयुवती एक सपना देखती है कि वह इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी में अपने जीवन को साकार कर सके और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जोड़ सकें। मैं मंत्री महोदय से दो चीजें जानना चाहता हूं। मेरे प्रश्न का "क" भाग है कि विश्व व्यापार संघ के साथ जो समझौता हो रहा है–खास करके विश्व व्यापार संघ के मोड और आईटी टेक्नोलॉजी बिजनेस के बारे में–ये मोड-1, मोड-2 और मोड-4 क्या हैं और उस समझौते का क्या असर पड़ेगा? मेरे प्रश्न का "ख" भाग है कि इस व्यापार में काफी कम्पीटीशन होने वाला है और वह कम्पीटीशन चाइना के साथ होने वाला है। उस वक्त जो हमारे मध्यवर्गीय परिवार के लोग अपने बच्चों को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में पढ़ा रहे हैं, कम्प्यूटर इंजीनियर बना रहे हैं, इनफार्मेशन टेक्नोलाजी पढ़ा रहे हैं, उनका भविष्य कहीं अधर में तो नहीं लटक जाएगा? क्या इस प्रतिस्पर्धा में, कम्पीटीशन में हमारे भारतीय नौजवान और नवयुवतियां पूरी तरह खरे उतर सकेंगे? इस संबंध में सरकार क्या सोच रही है?

श्री अरूण शौरी: सर, डब्ल्यूटीओ--मैं इसमें तो मास्टर्स यशवंत सिन्हा जी और अरूण जेटली जी हैं–इसमें मेन चीज़ यह है कि मेन फोकस जो अभी तक रहा है, on trade in commodities. And trade in services पर अभी there is only sporadic movement in this regard but when I had the opportunity to go recently to Montreal for the mini-ministerial meeting on negotiations as a prelude to Cancun मैंने इम्फेसिज से यह किया था कि आप कमोडिटीज पर यह सब करते रहते हो मगर जिन चीजों में हम स्ट्रांग बनते हैं, उन चीजों पर आप कोई भी मूवमेंट आगे नहीं दिखाते। सर्विसिज का एक ऐक्जाम्पल यह जरूर था। मैंने इलस्ट्रेट भी किया था कि आपके यहां जैसे लेजिस्लेशन इंट्रोडयूज हो रही है to prevent our professional from going and , secondly, जब भी वीज़ा की कैप्स आप लोयर कर रहे हो और तीसरा जहां कैप 95 हजार होता है, उतने वीज़ा भी ऐक्चुअली दिए नहीं जाते क्योंकि उस प्रोसेस को आप ईलान्गेट कर रहे हो because of pressure from within your societies.

सर, चार मोड्स हैं, आफ मीटिंग द सर्विस, जैसा अहलुवालिया साहब ने कहा। हम चारों पर इम्फेजाइज कर रहे हैं कि इन पर लिब्रलाइजेशन होना चाहिए। मोड-1 मुद्दा है of cross-border supply of a service which is analogous to the movement of goods. Mode 2 is, consumption abroad. For instance, if a child comes from Malaysia for learning medicine in the Pai Institutes in Manipal, then, that is, regarded as Mode 2. Even a tourist who comes here, is also being supplied a service within India. So, that becomes Mode 2. In Mode 3, there is a commercial presence, that is, the type of H1 visas that I have mentioned

and L1 visas, in which a company from India will set up an operation, say in the US or in Europe, and its professionals will be actually located in that country and they will supply that particular service as temporary residents in that country. The fourth is, Mode 4. That those who are service suppliers of a member country, that is, they are self-employed individuals who obtain their remuneration directly from the customers, not from a company which has been set up by India. इन चारों चीजों पर इम्फजाइज हुआ है क्योंकि Mode 4 is of the greatest interest to us where there should be free movement of individuals between countries as there is free movement of capital. They are always emphasising on movement of capital and they want access to our market. We say, you allow our professionals also freely to go there. अगर आप इजाजत दें तो मैं चाइना के बारे में बता दूं।

श्री सभापति: अभी दूसरे मैंबर्स प्रश्न पूछ रहे हैं। श्री रामचन्द्रैया।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, I am very glad that this potential field of information technology, which is going to make a major contribution to the GDP of this country, is being exploited by the Government. It is a very good thing that efforts are being made to exploit this field. But I want to draw the attention of the Government with regard to manufacturing of hardware in this country. Sir, the Government is committed to the *swadeshi* philosophy, and major banks are going for computerization. Banks, like State Bank of India, have advertised for procurement of hardware, naming the brand names of the multinational companies in this country. Companies like Wipro and HPCL, they are competing with the international products, and they have been listed for supplies in other countries. I do not know the reason why the State Bank of India and other premier banks have announced for procurement of this hardware, naming a particular brand name of a product. So, I want to bring to the notice of the Minister one thing. If at all, the Government is not committed to the policy of *swadeshi,* at least, a level playing field has to be created, and the brand names should not be announced. You engage companies which are capable of supplying the products. In this respect, I would like to submit that the Indian companies are competing with the international products. I bring this fact to the notice of the Government so that the Government may take steps to remove this anomaly and try to create a level playing field so that Indian companies also compete in this field. Otherwise, my apprehension is that the Indian industry is going to be migrated to other countries.

SHRI ARUN SHOURIE : Sir, that is a very important apprehension, and we share that, and that is why the Government, as you know, in its standard procedure has stated that there can be no specification of a kind which actually limits the tender to pre-selected suppliers in that sense. A few cases of this kind had been brought to the attention of the Government, including the Ministry of Information and Technology in some tenders, and some of the representatives of companies had come and met me also, and I think, we have issued a circular and reminders to all the persons in the Government departments that this practice should not be there. If the State Bank of India has issued some tenders, Sir, I will make an inquiry into this. We do not have the jurisdiction on that. That is an autonomous organization. But we will bring this fact to their notice.

As far as the migration is concerned, you are absolutely right. To prevent that migration, we must do much more by way of incentives for production of hardware in our country, and the Government is systematically working on this. There were 7-8 incentives given in the last Budget by Shri Yashwant Sinha in this regard, and we are also now setting up a Task Force, not of Government officials, because when we go and tell people: "Please come and invest here; India is a good country to invest in for hardware production," they may not believe us. But those people who have been successful in producing hardware in India, a Task Force is being constituted of them, and the Government will assist them so that they can go as leaders of Indian industry to those big companies, like INTEL and others, and invite them to come and set up production centres in our country because, we are people who can testify by our own success that, "Yes, it is possible to produce the highest technology stuff in India."

SHRI C. RAMACHANDRAIAH : Sir, what I am trying to say is this. Sir, this is a very important question *(Interruptions)* Sir, you see, we are entering into the WTO around 2005, and you are reducing the customs duty on import of hardware, and VAT system is being introduced where you cannot intervene with the State Governments. So ultimately, the product that is being imported into this country, is becoming cheaper compared to the Indian product because of the inconsistent policies of the State Governments and the Central Government. Why don't you create a level playing field where the Indian product also will compete?

SHRI ARUN SHOURIE : Sir, this is a very important point, that is, that India entered into an agreement quite some time ago that in the case of IT and electronic products, by the year 2005, there will be zero import duty regime, and in that sense, we will not get protective walls for nurturing our own units. Otherwise, when you have high import duties, it becomes difficult to import the components also, and then our secondary units cannot prosper and compete against other companies, giving you a complete product of a computer manufactured in Malaysia. So, the country is already committed to a zero duty regime, and the way we have to attract production facilities into the country, is by creating an environment and creating infrastructure which will make our firms more competitive, and I am very happy to report, Sir, right in Noida, we can go and see Mauzerbare, a company with exports already of almost 1,000 crores today. We would not have heard of a company called Tandon Electronics. Their exports, this year, are going to be almost Rs. 4,000 crores. Between these two companies alone, in hardware, we would be exporting almost a billion dollars—and that is the rate of growth—and it is these persons who are the best propagandists for India, who can go and convince people like Intel. Mr. Ahluwalia was just suggesting that we used the Intel brand. Sir, one of the largest R&D facilities of Intel is located in Bangalore, and, now, we have to persuade them that you please produce those chips also in India; do not just do the research here and produce the chips in Malaysia. So, it is that approach which will work.

*404. [The questioner (Shri H.K. Javare Gowda) was absent. For answer *vide* page 31 *infra*.]

*405. [The questioner (Shri Ghulam Nabi Azad) was absent for answer *vide* page 32 *infra*.]

* 406. [The questioners (Shri Santosh Bagrodia and Prof. Saif-ud-din Soz) were absent. For answer *vide* page 33 *infra*.]

* 407. [The questioner (Shri T.S. Bajwa) was absent. For answer *vide* page 33-34 *infra*.]